period 1984—87 due to their crops having not been insured;

(c) what advice has been given to these States; and

(d) whether there is any demand that cotton, jute, barley and gram be also covered by the Scheme; if so, what has been Governments response thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) The States|U.Ts. which have not vet introduced the Crop Insurance Scheme are Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Sikkhn, Rajasthan, Punjab, Haryana, Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep and Chandigarh. Rajasthan had participated in the scheme in Rabi 1985-86 and 'Kharif 1986 seasons but withdrew from the scheme thereafter.

(b) It is not possible to estimate the loss that the farmers have suffer in each of these Stated and Union Territories by way of non-receipt of insurance claims during the period 1984—87 because their crops were not insured..

(c) States and Union Territories are advised from time to time to implement the scheme.

(d) Gram is already covered under the Scheme. Due to heavy losses it has been decided to acquire more experience in imp'ementing the scheme before extending the coverage to other crops. There is also no demand to cover jute and bailey. States have been advised to frame their own schemes for extending insurance co verage to cotton out of their own budgetary resources. The State Governments can obtain reinsurance cover from the General Insurance Corporation of India (GIC) the terms and conditions of which could be finalised between the Government of India and the State Government.

वनस्पति के मूल्य

*367. **श्री रशीद मसूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों से वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि होती रही है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1987 से जुलाई, 1987 के बीच वनस्पति के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने वनस्पति के निर्माताओं को समय-समय पर उनकी आवश्यकतानुसार आयातित खाद्य तेल की आपूर्ति की है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मूल्य के क्या कारण है ; और

(ङ) क्या सरकार वनस्पति का अधिकतम मूल्य घोषित करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जुलाई, 1987 को समाप्त पिछले छः महीनों में वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक में 5% की वृद्धि हुई है ।

(ग) वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेल का आवंटन जनवरी, 1987 में उनकी आवश्यकता के 10% से लेकर जुलाई, 1987 में 10% तक भिन्न-भिन्न मात्रा में किया गया है ।

(घ) जैसाकि वनस्पति उद्योग ने सूचित किया है, मूल्यों के बढ़ने का मुख्य कारण निवेशों की लागत में हुई वृद्धि है, जिसमें देशीय खाद्य तेलों की लागत भी शामिल है ।

(ङ) इस मामले पर आगे और विचार किया जा रहा है ।

Contaminated Water Supply in Delhi

'368. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state: